वेदन प्राप्त हुआ है कि उनका २१०–१०–२६०–१५–४२५ रु० का वेतन-क्रम संशोधित करके २१०–१०–२७०–१५–४३५ किया जाना चाहिये क्योंकि १६०–१०–३३० के पुराने वेतन-क्रम की तुलना में उन को नये वेतन-क्रम में क्रमशः पहले और दूसरे साल लगातार दो साल १० रु० और ५ रु० की हानि होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी यह प्रार्थना स्वीकार करने का विचार है, और यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां । तकनीकी सहायकों और ऐसी ही कुछ दूसरी श्रेणियों के कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे । संशोधित वेतन-मान में जब वेतन ३२० रुपये और ३३५ रुपये पर पहुंचता है (संशोधित वेतन-मान के पहले और दूसरे वर्ष में नहीं) तो पुराने वेतन-मान की तुलना में १० रुपये और ५ रुपये का नुकसान होता है, क्योंकि तनख्वाह के इन स्तरों पर पहुंचने पर महंगाई भत्ते की दर कम हो जाती है ।

(ख) और (ग). वेतन-मान में संशोधन करने का विचार नहीं है क्योंकि इसी कारण से दूसरी श्रेणियों के कर्मचारियों को भी ऐसा ही नुकसान रहता है । इस नुकसान से बचने के लिए सम्बद्ध कर्मचारियों को यह छूट भी दी गयी थी कि यदि वे चाहें तो १-७-१९५९, यानी संशोधित वेतन-मान लागू होने की तारीख के बाद किसी भी उचित तारीख से संशोधित वेतन-मान स्वीकार कर सकते हैं ।

Shortage of Iron Sheets in Punjab

2009. Shri Daljit Singh: Will the Minister of **Works, Housing and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is acute shortage of corrugated iron sheets for roofing houses in Punjab; and

(b) if so, the steps being taken to evolve substitute material within easy reach of people?

The Minister of Works, Housing and Rehabilitation (Shri Mehr Chand Khanna): (a) Yes.

(b) Provision has been made in the expansion programme of the Rourkela Steel Plant for production of 1,60,000 tonnes of galvanised sheets. Two private firms have also obtained licenses for establishment of factories for the manufacture of asphaltic corrugated sheets from bitumen, a bye-product of the Refinery Industry.

Slum Clearance in Delhi

2010. Shri Maheswar Naik: Will the Minister of **Works, Housing and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number of slum-dwellers in Delhi who have been allotted land for housing purposes under the Jhuggi-Jhonpri Scheme for clearance of slums;

(b) whether it is a fact that several slum-dwellers from Rajasthan who had been given land under the scheme have sold their plots; and

(c) if so, the action taken in the matter?

The Minister of Works, Housing and Rehabilitation (Shri Mehr Chand Khanna): (a) 7,829 plots (4,264 of 25 square yards each and 3,565 of 80 square yards each) have so far been allotted under the Jhuggi and Jhonpri Removal Scheme to squatters on Government and Public lands in Delhi.

(b) No record about the States from which the squatters/allottees hail is maintained. It has however been reported that about 300 plots have changed hands.

(c) Show-cause notices have been issued in all cases. Allotments of about 200 allottees have been cancelled and steps are being taken to resume possession.